



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

7 चैत्र 1933 (श0)  
(सं0 पटना 97) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2011

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 मार्च 2011

एस0ओ0 25, दिनांक 28 मार्च 2011—मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (1994 का अधिनियम सं0-10) की धारा-30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत दायरवादों के त्वरित विचारण हेतु मानवाधिकार न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

2. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2010/1607/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव।

18 मार्च 2011

एस0ओ0 26, एस0 ओ0 25, दिनांक 28 मार्च 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2010/1607/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र

सरकार के सचिव।

*The 18th March 2011*

S. O. 25, dated the 28th March 2011—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No. 10 of 1994) the State Government, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to designate the court of 1st Additional District and Session Judge in each of the session division of the state as Human Rights Court for the speedy trial of the cases under the Protection of Human Rights Act, 1993.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication of notification in Gazette.

(File No.-A/Act-07/2010/1607/J.)

By Order of the Governor of Bihar,  
RAJENDRA KUMAR MISHRA,

*Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 97-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>